इस विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का जोरदार विरोध किया । भारतीय श्रम सम्मेलन ने अप्रैल, 1990 में इस मामले पर विचार-विमर्श किया और यह सिफ़ारिश की कि उपरोक्त विधेयक वापस ले लिया जाए और नए औद्योगिक संबंध कानून के लिए विशिष्ट प्रस्तावों को तैयार करने के लिए एक समिति गठित की जाए, जिसमें केन्द्रीय ट्रेड यूनियन और नियोजक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों । तदनुसार, यह विधेयक 30 मई, 1990 को वापिस ले लिया गया तथा 8 मई, 1990 को एक द्विपक्षीय समिति गठित की गई थी । सरकार इस मामले में उन सिफ़ारिशों को, जो समिति द्वारा की जाएंगी ध्यान में रखते हुए अपना दृष्टिकोण बनाएंगी । इस अवस्था पर यह बताना संभव नहीं है कि इस संबंध में कानून के लिए प्रस्ताव संसद के समक्ष कब प्रस्तुत किया जाएगा ।

महिलाओं से संबंधित कानूनों को लागू करने वाले तंत्र को सुदृढ़ किया जाना

1152. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों को लागू करने वाले तंत्र को सुदृढ़ करने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) महिला श्रमिकों और बाल श्रमिकों से संबंधित प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए कुछ राज्यों में प्रायोगिक आधार पर योजना शुरु की गई है। इस योजना में 50% केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है जबकि शेष व्यय को संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को भी संशोधित किया गया था ताकि कुछ चुने हुए स्वैच्छिक संगठन अधिनियम के उल्लंघन के बारे में शिकायतें दर्ज करा सकें।

अधिकांश मामलों में, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों के प्रवर्तन के लिए समुचित सरकारें हैं । केन्द्रीय सरकार महिलाओं से संबंधित श्रम कानूनों के कारगर कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध करती रही है ।

मानव आवास प्रबंध संस्थान की स्थापना

1153. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी आलिया :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगर विकास निगम ने हाल ही में अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से मानव आवास प्रबंध संस्थान की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के संस्थान की स्थापना का क्या उद्देश्य है; और

(ग) यह संस्थान किस सीमा तक आवास सुविधाएं उपलब्ध करा पाने में सफल हो सकेगा ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) और (ख) हुडको द्वारा मानव बस्ती प्रबंध संस्थान (एच० एस० एम० आई०) की स्थापना 1985 में की गई थी । इन्डो-डच करार के अंतर्गत भारतीय मानव बस्ती कार्यक्रम आवास अध्ययन संस्थान रोटरडम के सहयोग से मानव बस्ती प्रबंध संस्थान को सौंपा गया है । मानव बस्ती प्रबंध संस्थान की